of a 3 MMTPA capacity grass-root refinery at Mangalore as a Joint Venture, between HPC1 and Indian Rayon Industries Limited. The implementation of the Mangalore Refinery project is in progress and actual physical progress as on September, 1995 was about 90%.

(b) The project is expected to be completed by June, 1996.

(c) The revised estimated cost is about Rs. 2593 crores, including FE component of Rs. 944.20 crores.

'Plundering of Money by Van Vibhag in U.P.'

2387. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that Van Vibhag in all the districts in U.P. are involved in plundering money and are doing little towards environment and forests; and

(b) if so, the steps being taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI RAJESH PILOT): (a) and (b) The information is being sought from the State Government of UP and will be laid on the Tabic of the House.

Payment of Environmental Rent

2388. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether India has demanded that Western countries should pay "environmental rent" for the excessive emission of Green House cases;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the reaction of the Western countries on this demand?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI RAJESH PILOT): (a) and (b) The argument pertaining to environment rent' has been advanced by India in the nature of stressing the point that the developed nations have excessively utilised the common resource of atmosphere in the past and continue to do so. The estimates of the 'environmental rent' worked out by Indian researchers are of the order of US dollars 70 billion equivalent per year.

(c) Western countries have not formally made known their reaction.

मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में संचार सुविधायें उपलब्ध करना

2389. **श्री अजीत जोगी**: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना केन्द्रीय सरकार को भेजी हैं;

(ख) यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;और

(ग) उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

पत्तनों में गाद का भरना

2390. **श्री नरेश यादव**: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न पत्तनों में समुद्र तल में भर रही गाद को निकालने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रबंध किये गये हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के पास इस प्रयोजनार्थ कोई तंत्र हैं;और

(ग) यदि नहीं तो भारत सरकार ने किन-किन देशों को इस कार्य के संबंध में ठेका दिया हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम.राजशेखर मूर्ति): (क) और (ख) भारत सरकार ने देश में विभिन्न पत्तनों की निकर्षण संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम,भारतीय निकर्षण निगम(डी.सी.आई) की स्थापना की हैं। इसके अतिरिक्त ,कुछेक महापत्तनों को उनके नियंत्रण में आने वाले क्षेत्र से गाद निकालने के लिए निकर्षण उपकरण उपलब्ध करवाए गए हैं।

।